S. No.	Name of the Project	Estimated cost
8.	Cafeteria and two rooms at Bundi	8.00
9.	Provision of Cafeteria at Deeg Palace	2.00
10.	Provision of Cafeteria at Osian	2.00
11.	Yatri Niwas at Jodhpur	36.00
12.	Floodlighting of Jaisalmer Fort	11.60
13.	Trekking Huts and equipment for Mt. Abu	5.00
14.	Tourist Complex at Chandravati	4.50
15.	Construction of Tourist Complex at Nakki Lake (Mt. Abu)	6.00
16.	Construction of a Cafeteria at Menal	4.96
17.	Development of island and tourist resort at Jaisamand Lake	12.93
18.	Tourist Complex at Bundi	7.44
19.	Provision of Kiosk at Baddi (Kota)	3.88
20.	Construction of Cafeteria at Alaniya	4.28
21.	Construction of Tourist Bungalow at Jhalawar	11.28
22.	Provision of Kiosk at Chandra Bhaga (Jhalawar)	2.05
23.	Tourist Complex at Deeg	16.63

(c) The Department will consider financial assistance for these projects subject to merits of the proposal, potential of the place, existing infrastructure, existing and projected tourist traffic, viability of the project, availability of funds and inter-se priorities.

(d) Does not arise.

पाठ्य पुस्तकों/अभ्यास पुस्तिकाओं की कीमतों में वृद्धि

812. श्री कपिल वर्मा :
श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में रियायती कागज के कोटे को घटा कर आधा कर दिये जाने के बाद, अभ्यास-पुस्तिकाओं और पाठ्य-पुस्तकों की कीमतों में वृद्धि हुई है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या एक सरकारी कम्पनी हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने, जो रियायती कागज की सप्लाई करती है, केन्द्रीय सरकार से कागज की कीमत बढ़ा देने की मांग की है;

(ग) क्या "कागज नियंत्रण आदेश" के रद्द किये जाने के पश्चात राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराये जाने वाले कागज की मात्रा में वास्तव में कोई कमी आई है ; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी राज सहायता प्रदान की गयी तथा रियायती कागज की कीमतों की बाबत क्या दर-सूची निर्धारित की गयी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल.पी. साही) : (क) शैक्षणिक क्षेत्र के कागज की समय पर पूर्ति को सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुये और इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि कागज नियंत्रण आदेश के निरस्त

होने से पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं आदि पर अनुचित प्रभाव न पड़े, 24 करोड़ रुपये के वार्षिक आवंटन सहित एक आर्थिक सहायता योजना आरम्भ की गयी थी। प्रति मीट्रिक टन के लिये यह सहायता राशि 3000/- रुपये की दर से दी जाती है। एक वर्ष में 80,000 मीट्रिक टन कागज राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वितरण के लिये उपलब्ध कराया जा सकता है। रियायती कागज से तैयार की गयी स्कूली पाठ्य पुस्तकों और अभ्यास पुस्तिकाओं के मूल्यों का निर्धारण रियायती कागज की कीमतों के संदर्भ में किया जाता है। जनवरी, 1987 से आर्थिक सहायता योजना के आरम्भ होने के पश्चात रियायती कागज की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) जी, हां।

(ग) कागज (उत्पादन का नियंत्रण) आदेश, 1978 के अन्तर्गत वर्ष 1986 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में शैक्षणिक क्षेत्र के लिये आवंटित सफेद मुद्रण कागज की कुल मात्रा लगभग 1.50 मीट्रिक टन थी। तथापि मिलों द्वारा की गयी वास्तविक आपूर्ति किये गये आवंटनों का मात्र 50 प्रतिशत के लगभग थी। तथापि, आर्थिक सहायता की योजना के अन्तर्गत एक वर्ष में राज्यों को वितरण करने के लिये 80,000 मीट्रिक टन कागज उपलब्ध कराया जाता है। सहायता की इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 के दौरान कागज की आपूर्ति किये गये आवंटनों की मात्रा प्रायः समान ही रही है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण पिछले बकाया कागज की आपूर्ति में 1988-89 में कुछ रुकावट आयी है। इस संबंध में उद्योग मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया है कि शैक्षिक क्षेत्र को कागज की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

(घ) जनवरी, 1987 में आर्थिक सहायता की योजना को आरम्भ किया गया है। अब तक आर्थिक सहायता की दर 3000/- प्रति मीट्रिक टन रही है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कागज 7560/- रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से मिलता रहेगा।

Books missing from Delhi Public Library

813. SHRI KAPIL VERMA:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at least 32,118 precious books are missing from Delhi Public Library since 1980; if so, when was the last verification of books conducted and what are the details thereof;

(b) since when and the reasons for which the verification of other stores of the capital's network of reading rooms and mobile vans has not been conducted; and

(c) how much grants-in-aid have been given for the purchase of library books and what is the total number of books purchased and expenditure incurred during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) Yes, Sir, 32,118 books were reported missing in the last stock verification done in 1980. Since 1985, another stock verification is in progress.

(b) The verification of stores items was taken up in 1975. However, stock verification of these items after 1975 could not be taken up due to shortage of staff.